Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding fixing price of forest produce in Chhattisgarh-laid.

श्री मोहन मंडावी (कांकेर): छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय वनोपज़ का संग्रहणकर्ताओं को उचित मूल्य दिया गया, ऐसा कहा गया है । यह दावा वास्तविकता से परे है । कोरोना काल मे हाट -बाजार पूरी तरह से बंद थे । लेकिन योजनाबद्ध तरीके से वनोपज़ को व्यापारियों तक पहुचाया गया । छत्तीसगढ़ राज्य महुआ फूल, इमली, गोंद और तेंदुपत्ता जैसे अनेक वनोपज़ मे एशिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ।

वनोपज़ का संग्रहण कर उसके व्यापार करने पर सरकारी आकड़ों के अनुसार करीब एक हजार करोड़ कि वार्षिक आमदनी होती है । सामान्य समय मे बाजार खुलने पर वनोपज़ का संग्रहण कर जीविकापार्जन करने वाले आदिवासी भोले-भाले लोगों से वनोपज कम दामों मे खरीद कर कोरोना के संकट काल मे इनका दोहन और शोषण कर उनके हक का हनन हुआ है और व्यापारी वर्ग को फायदा पहुंचाया गया । मैं सरकार का ध्यान इस बात पर आकृष्ट करता हूँ कि पुन: वनोपज संग्रहणकर्ताओ को आने वाले वर्षों मे नुकसान न हो इस लिहाज से छत्तीसगढ़ मे वनोपज का उचित मूल्य निर्धारित कर संग्रहकों को लाभ दिया जाए ।